

दि कार्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 24

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 31 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास रहा....



वो तारीख जब हमारा भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया था। जिसने इससे पहले न जाने कितनी कुर्बानियां देखीं, बलिदान और भारत माता के वीर सपूतों तो अपने अमूल्य प्राण न्योछावर करते देखा। इसी दिन हमारा संविधान भी तैयार हुआ था। वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती हैं। 75 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते

हैं। उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां पर हुईं और आयोजन भी अच्छा हुआ। भारतीय जवान इस कंकणपाती ठंड में फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास भी रहा

संविधान बनने की शुरुआत

भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है लेकिन वजह संविधान के अलावा भी कुछ है। दरअसल, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद, हमारा देश अभी तक एक आधिकारिक संविधान के बिना था। इसीलिए, 29 अगस्त 1947 को

संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नेतृत्व डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने किया और इसमें के.एम. मुंशी, मुहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, एन. माधव राव, और टी.टी. कृष्णामाचारी जैसे बड़े दिग्गज शामिल थे।

26 जनवरी को बना अपना संविधान

फिर आया 4 नवंबर 1947, एक महत्वपूर्ण दिन जब भारत के भविष्य को दिशा देने वाले दस्तावेज ड्रॉ संविधान का मसौदा तैयार होकर संविधान सभा के सामने पेश किया गया। अगले दो सालों में संविधान सभा ने कई बैठकें कीं, इस मसौदे पर चर्चा की, कई बदलाव किए

और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 308 सदस्यों ने संविधान की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। इस कदम ने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन कानून (1935) की जगह अब भारत का अपना संविधान देश का मुख्य

कानूनी दस्तावेज बन चुका था। हालांकि, संविधान सभा ने तय किया कि संविधान को लागू करने के लिए दो दिन और इंतजार किया जाएगा। अगले दो दिनों में ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपने संविधान का गौरव मनाते हैं।

26 जनवरी चुनने के पीछे यह थी वजह

संविधान सभा ने इस उद्देश्य के लिए 26 जनवरी को चुनते हुए,

राष्ट्रीय गौरव के पर्याय के रूप में एक दिन पर दस्तावेज को स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इस तिथि का महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (दृष्ट) से मिलता है। कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र के दौरान 26



जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) के दिन के रूप में नामित किया था, जिसमें सभी भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। आई. एन. सी. का निर्णय भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी। इस सत्र के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया था। बीस साल बाद, 26 जनवरी को ही देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और तबसे देश इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आया है।



द कार्मिक पोस्ट समाचार पत्र की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ....

- संपादक

वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए जन अभियान होगा प्रारंभ सीएनजी एवं ई-व्हीकल को करें प्रोत्साहित, ई-चार्जिंग स्टेशन होंगे प्रारंभ - प्रभारी कलेक्टर श्री शुक्ला



सागर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए जन अभियान प्रारंभ होगा, सीएनजी एवं ई व्हीकल को प्रोत्साहित करें एवं ई-चार्जिंग स्टेशन प्रारंभ होंगे। उक्त निर्देश प्रभारी कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने शहर परिवेश की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु सिटी क्रियान्वयन समिति की बैठक में दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री के.पी. सोनी, श्री आरके जैन, श्री संजय तिवारी, श्रीमती रीता कुरेशिया, डीएसपी ट्रैफिक श्री अखिलेश तिवारी, लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्रभारी कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने आज शहर की परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार

हेतु गठित स्थिति क्रियान्वयन समिति में निर्देश दिए कि शहर की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए जन अभियान प्रारंभ किया जाएगा जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित शहरवासियों को शामिल कर वायु गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वप्रथम कचरा न जलाया जाए। संपूर्ण सड़कों के दोनों तरफ फेवर ब्लॉक लगे, साथ में जगह-जगह पार्क, वृक्षारोपण एवं फाउंटन लगाने का कार्य किया जावे। उन्होंने कहा कि ई-वाहन एवं सीएनजी के लिए प्राथमिकता के साथ उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जो ऑटो अपनी आयु पूरे कर चुके हैं उनकी जांच कर कार्रवाई की जाए। प्रभारी कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में स्वीपिंग मशीन स्पाइलग मशीन का प्रयोग सफाई में किया जावे साथ में लकड़ी, कोयला के उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से अधिक से अधिक सभी पात्र हितग्राहियों को गैस टंकी उपलब्ध कराई जाएं जिससे की लकड़ी का प्रदूषण कम होगा। प्रभारी कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत शहर की परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन के दौर में मौसम और फसलों के बारे में पुरखों का ज्ञान आ सकता है काम

ऐतिहासिक साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जलवायु में आते बदलावों से निपटने के लिए फसलों और जल प्रबंधन को लेकर रणनीतियां बनाई थीं भले ही वैज्ञानिक रूप से हम अपने पुरखों से कहीं आगे हैं लेकिन समय के साथ उन्होंने जो समझ विकसित की थी, वो आने वाले भविष्य में भी जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐतिहासिक साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जलवायु में आते बदलावों से निपटने के लिए फसलों और जल प्रबंधन को लेकर रणनीतियां बनाई थीं। यही वजह है कि वो बारिश की कमी के बावजूद बाजरा जैसे छोटे अनाज की पैदावार हासिल करने में कामयाब रहे और उनकी सभ्यता हजारों वर्षों तक फलती-फूलती रही।

इस बारे में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (बीएसआईपी) के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया है, जिसके नतीजे जर्नल क्वाटरनेरी साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस शोध में वैज्ञानिकों ने गुजरात के वडनगर का पुरातात्विक अध्ययन किया है। यह एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र है। बता दें कि वडनगर एक अत्यंत प्राचीन शहर है, जहां हजारों वर्ष पहले भी खेती की जाती थी। वैज्ञानिकों को भी वहां 2500 वर्षों तक मानव सभ्यता के फलने-फूलने के साक्ष्य मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी जांच की है कि वहां इस दौरान पर्यावरण और जलवायु में कैसे बदलाव आए थे। इन्हें समझने के लिए उन्होंने ने पुरातात्विक निष्कर्षों, पौधों और वनस्पति से जुड़े आंकड़ों और आइसोटोप का उपयोग किया है। अध्ययन में पिछले करीब 2000 वर्षों के दौरान बारिश में आए बदलावों और उनके प्रभावों को समझने का प्रयास किया गया है। वहां बारिश में आए इन बदलावों के साथ फसलों, वनस्पति और संस्कृति में भी किस तरह बदलाव आया था, वैज्ञानिकों ने इसको भी उजागर किया है, ताकि यह समझा जा सके कि अतीत में लोग जलवायु में आते बदलावों का किस तरह सामना किया करते थे। इस रिसर्च के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक जलवायु में बदलाव के बावजूद, लोगों ने अपने द्वारा उगाई जाने वाली फसलों में फेर बदल करके जलवायु में आते बदलावों के प्रति अनुकूलन किया था। अध्ययन के मुताबिक इस साइट पर जो चीजे मिली हैं वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच सात अलग संस्कृतियों के क्रमिक इतिहास को दर्शाती हैं। वहां इतिहास में उगाई जाने वाली फसलों के जो साक्ष्य सामने आए हैं उनके मुताबिक प्राचीन और मध्य युग के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था, जिस वजह से उस समय बड़े दाने वाले अनाज उगाए जाते थे। लेकिन मध्यकाल के बाद करीब करीब 1300 से 1850 ईसा पूर्व वहां लोगों ने बाजरा जैसे मोटे अनाज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।



भागलपुर, सहरसा में गैस चैम्बर से हुए हालात, दिल्ली में भी 400 के करीब पहुंचा एक्वआई



भागलपुर- भागलपुर-सहरसा में बढ़ता प्रदूषण आपात स्थिति में पहुंच गया है। इन दोनों शहरों में हालात यह है कि लोगों के लिए सांस लेना तक दुश्वार हो गया है। ऐसा लगता है कि वो किसी गैस चैम्बर में रह रहे हैं। भागलपुर में बढ़ते प्रदूषण का आलम यह है कि वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्वआई) बढ़कर 432 पर पहुंच गया है। इसी तरह सहरसा में भी एक्वआई 408 रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि प्रदूषण के मामले में भागलपुर सबसे अक्वल है, लेकिन दिल्ली भी उससे कोई ज्यादा पीछे नहीं है। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 392 पर पहुंच गया है। इसी तरह देश के 26 अन्य छोटे शहरों में वायु गुणवत्ता जानलेवा बनी हुई है। कुल मिलकर देखें तो देश के छोटे शहरों में प्रदूषण से स्थिति कहीं ज्यादा खराब हो गई है।

आंकड़ों के मुताबिक जहां अगरतला में वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अंगुल (316), अररिया (399), आरा (336), आसनसोल (324), औरंगाबाद (बिहार) (323), बिहारशरीफ (320), बर्नीहाट (376), चंडीगढ़ (353), छपरा (354), देहरादून (314), धौलपुर (345), फरीदाबाद

(316), गाजियाबाद (313), ग्रेटर नोएडा (374), गुरुग्राम (320), हाजीपुर (304), हनुमानगढ़ (304), करौली (335), मुजफ्फरनगर (360), मुजफ्फरपुर (324), नोएडा (341), पटना (358), पूर्णिया (335), राजगीर (335), समस्तीपुर (339) और श्रीगंगानगर (327) में भी हवा जानलेवा बनी हुई है। इसी तरह 46 अन्य शहरों में भी हालात दमघोंटू बने हुए हैं। वहीं तिरुपति-विजयपुरा सहित 12 शहरों में हवा साफ है। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे कम दर्ज किया गया है। भरतपुर-किशनगंज सहित 46 शहरों में प्रदूषण का स्तर दमघोंटू (201-300 के बीच) रहा, जबकि पटना-श्रीगंगानगर सहित 28 शहरों में प्रदूषण का स्तर जानलेवा (301-400 के बीच) है। वहीं भागलपुर (432) और सहरसा (408) में हालात आपात बने हुए हैं।

यदि दिल्ली की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता %बेहद खराब% श्रेणी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 35 अंक बढ़कर 392 पर पहुंच गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में इंडेक्स 316, गाजियाबाद में 313, गुरुग्राम में 320, नोएडा में 341, ग्रेटर नोएडा में 374 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के %मध्यम% स्तर को दर्शाता है। जबकि लखनऊ में यह इंडेक्स 226, चेन्नई में 98, चंडीगढ़ में 353, हैदराबाद में 78, जयपुर में 148 और पटना में 358 दर्ज किया गया। देश के महज जिन 12 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे नीचे यानी %बेहतर% रहा, उनमें अरियालूर 40, बागलकोट 50, चामराजनगर 49, कुड्डलोर 44, गंगटोक 43, कडपा 47, मदिकेरी 43, पालकालाइपेरूर 47, शिवसागर 48, थूथुकुडी 48, तिरुपति 48, और विजयपुरा 39 शामिल रहे।

प्रत्येक जिले में लगेंगे वन मेले - वन मंत्री श्री चौहान

हर्बल उत्पादों की बिक्री 60 लाख तक पहुंची, 10 हजार लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

भोपाल प्रदेश के प्रत्येक जिले में वन मेलों का आयोजन होगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने आज राज्य स्तरीय वन मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे वन मेले में पहली बार शामिल हुए और जनजातीय बंधुओं द्वारा संग्रहित जड़ी-बूटियों और हर्बल उत्पादों को देखकर अभिभूत हुए। वन मंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन मेले में 50 हजार से अधिक लोगों ने भागीदारी की और सिर्फ चार दिनों में ही हर्बल उत्पादों की बिक्री लगभग 60 लाख तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मेले में जानकार वैद्यों द्वारा लगभग 10 हजार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

वन मंत्री ने कहा कि मेले के माध्यम से लोगों को जड़ी-बूटियों की जो जानकारियाँ प्राप्त हुईं उससे आयुर्वेद अपनाने के प्रति रुझान बढ़ेगा। साथ ही जनजातीय परिवारों को जीविका चलाने के लिये सतत अवसर मिलेंगे।

सामाजिक न्याय, उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि दूर अंचलों के वनों से जड़ी-बूटियाँ संग्रहित करने वाले जनजातीय परिवारों को कठिन मेहनत करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा जड़ी-बूटियों का परीक्षण और प्रसंस्करण कर औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये लाभकारी होती हैं। उन्होंने कहा कि इन औषधियों का लाभ जनता को मिले और आदिवासी सशक्त हों।

वन, पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि वन मेले में आये आदिवासी संग्रहकों को पहचान मिलती है और उन्हें वनौषधि विक्रय के लिये एक मंच उपलब्ध होता



है। वन, पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में गरीबों के कल्याण का जो सपना है, वह ऐसे मेलों से मूर्त रूप लेता है। उन्होंने कहा कि स्टॉलों में कलाकृतियों और चित्रकला को देखकर मन प्रसन्न हो गया। मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि महत्वपूर्ण आयोजनों से प्रदेश विकास के नये रास्ते तय करेगा और सफलता के शीर्ष तक पहुँचेगा। वन मेला समापन समारोह में वन मंत्री श्री चौहान, उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाह और वन राज्य मंत्री श्री अहिरवार द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये, जिनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी सर्वश्रेष्ठ विक्रेता एवं सर्वश्रेष्ठ सजावट थे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी में एमएफपी पीएआरसी, सोशल फॉरेस्ट्री एवं बायोडायवर्सिटी बोर्ड को पुरस्कार दिया गया।



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



विकास के अमृत काल में संवैधानिक मूल्यों के साथ
रामराज्य की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | सशक्त और आत्मनिर्भर नारी शक्ति | अंत्योदय उत्थान
समृद्ध होता अन्नदाता | सक्षम युवा | सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं | सांस्कृतिक समृद्धि

75^{वें} गणतंत्र दिवस
की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं...

“ आइये, हम सब मिलकर मध्यप्रदेश को एक ऐसे गणतंत्र के रूप में लेकर आगे बढ़ें, जो सुराज, सुशासन सम्मत कार्यशैली और रामराज्य के आदर्शों का द्योतक हो, जिसमें सबका हित - सबका मंगल समाहित हो। शुभकामनाएं। ”

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

D18508/23